RESEARCH REVIEW JOURNALS
Volume-04
Issue-09
September-2019

ISSN: 2455-3085 (Online)
RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary
www.rrjournals.com[Peer Reviewed Journal]

नेपाल में बढ़ता पाकिस्तानी प्रभाव एवं भारत विशेष सन्दर्भ में: अवलोकन

Dr. Vishal Singh

Assistant Professor, S.R.S.PG. College, Kumhar, Bharatpur, Rajasthan (India)

ARTICLE DETAILS

Article History
Published Online: 16 Sep 2019

Keywords
आर.डी.एक्स., आई.एस.आई., रॉ, माओवादियों, शिखर सम्मेलन, प्रतिनिधियों।

ABSTRACT

काठमाण्डू से प्रकाशित नेपाली पत्रिका 'राष्ट्रीय मंच' ने अपने जनवरी 2002 के अंक में लिखा है कि "नेपाल में भारत विरोधी भावना कुछ वर्षों से है और इसके कई कारण है–पुरानी पंचायत व्यवस्था मूलतः भारत विरोधी भावना पर आधारित थी। राष्ट्रवाद के नाम पर इस व्यवस्था के लोग भारत का विरोध करते थे और प्रजातन्त्र के नाम पर नेपाली कांग्रेसी का। नेपाल में किसी संस्था या कार्य की राष्ट्रभक्ति का एक ही पैमाना है कि उसने कितनी बार भारतीय मूल्यों और सिद्धान्तों के खिलाफ आवाज उठाई है। परन्तु चिन्ता की बात यह नहीं। चिन्ता की बात यह है कि इस स्थिति का लाभ एक तीसरा देश पाकिस्तान उठाता है। उदाहरण के तौर पर रितिक रोशन काण्ड के दौरान देश भर में भारत के खिलाफ प्रदर्शन और हिंसक घटनायें हुई। बाद में नेपालियों को पता चला कि इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। बहरहाल इससे नेपाल को ही ज्यादा नुकसान हुआ। रितिक रोशन काण्ड से नेपाल के मद्धेशियों और गैर मद्धेशियों के बीच कटुता बढ़ गई तथा नेपाल का पर्यटन व्यवसाय संकट मे पड़ गया। इसी प्रकार अब भारत और चीन के बीच विवाद बढ़ गया था तो उस समय नेपाल के कुछ नेता जो अपने को राष्ट्रवादी कहते थे वास्तव में चीन की तरफ झुक गये थे और भारत विरोधी लहर को हवा दे रहे थे। परन्तु इस सारी स्थिति के लिए केवल नेपाल ही जिम्मेदार नहीं। भारत ने भी कई भूले की हैं। नेपाल में इस बात को लेकर बहुत ही हो–हल्ला मचाया गया कि भारत द्वारा सियासवाल खुर्दलोटन बांध के निर्माण से 'लुम्बिनी' डूब जायेगी। भारत सरकार समय से नेपाल को नहीं समझा सकी कि ऐसी कोई बात नहीं। 'लुम्बिनी' को कोई खतरा नहीं है।"

'काठमाण्डू पोस्ट' के दिनांक 06.09.2001 के अंक में प्रत्युष ओटा के लेख में कहा गया है कि "भारत नेपाल में पाकिस्तानी खुफिया एजेन्सी आई.एस.आई. का जो मामला उठाता है, वह कश्मीर में उसकी हताशा का प्रतीक है। भारत सरकार पाकिस्तान से मिलकर इस समस्या का समाधान निकालने की बजाय आसानी से आरोप लगाती है कि नेपाल में आई.एस.आई. के लोग सक्रिय है। प्रत्युष ओटा ने यह भी कहा है कि "अगर नेपाल में आई.एस.आई. सक्रिय है तो क्या, भारतीय खुफिया एजेन्सी 'रॉ' भी यहा वही काम कर रही है।"

दुनिया भर में खुफिया एजेन्सीज काम करती है, इसमें कोई अनहोनी बात नहीं। पर अभी तक नेपाल में 'रॉ' का कोई एजेन्ट आई.एस.आई. के साथ नहीं पकड़ा गया जबकि नेपाल में नेपाली पुलिस ने ही पाकिस्तानी दूतावास के कई जिम्मेदार अफसरों को आर.डी.एक्स. के साथ गिरफ्तार किया है। आखिर नेपाल में पाकिस्तानी दूतावास के अधिकारी आर.डी.एक्स. क्यो रखते है। अगर केवल पकड़े गये मामलों के तथ्यों और आंकड़ों पर जाये और किसी प्रकार का अनुमान न लगाये तो भी यह स्पष्ट है कि विभिन्न मौकों पर नेपाली पुलिस ने काठमाण्डू में अब तक पाकिस्तानी नागरिकों से लगभग दो सौ किलोग्राम आर.डी.एक्स. बरामद किया है जो काठामाण्डू घाटी जैसे दस शहरों को बरबाद करने के लिए पर्याप्त है।

दिनांक 13 अप्रैल 2001 को काठमाण्डू स्थित पाकिस्तानी दूतावास के प्रथम सचिव मोहम्मद अर्शद नीमा के निवास स्थान से सोलह किलोग्राम आर.डी.एक्स. बरामद किया गया। उसी आधार पर नेपाल सरकार ने उन्हें तुरन्त नेपाल छोड़ने का आदेश दिया। कुछ लोगों का ख्याल है कि आर.डी. एक्स. का यह जखीरा नेपाल के माओवादियों को दिया जाने वाला था। आश्चर्य इस बात पर है कि पाकिस्तानी दूतावास ने नेपाल पुलिस पर आरोप लगाया कि उसने पाकिस्तानी दूतावास के अधिकारी के निवास से आर.डी.एक्स. बरामद करके 'वियना कन्वेशन' का उल्लंघन किया है।

दिनांक 1 जनवरी, 2002 को जब काठमाण्डू में 'सार्क शिखर सम्मेलन' हो रहा था, तो पाकिस्तानी दूतावास के एक कर्मचारी सिराज अहमद को नेपाल पुलिस ने पारी संख्या में जाली डालरों और जाली भारतीय रूपयों के साथ पकड़ा। इसके पहले कि उसके खिलाफ पुलिस कार्यवाही करे, पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने नेपाल नरेश ज्ञानेन्द्र से बात की और कहा कि 'सार्क शिखर सम्मेलन' के दौरान सिराज अहमद को गिरफ्मारी से पाकिस्तान की बड़ी बेइज्जती होगी। बहरहाल उस समय सिराज को छोड़ दिया गया। किन्तु बाद में इस मामले की जाँच की गई और यह पाया गया कि सिराज अहमद दोषी था एवं उसके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए। इसके पहले कि कार्यवाही प्रारम्भ हो विदेश विभाग के अधिकारियों ने पाकिस्तान राजदूत को सलाह दी

RRIJM 2015, All Rights Reserved

कि सिराज को पाकिस्तान भेज दिया जाय और वह अन्ततः दिनांक 8 फरवरी, 2002 को पहली फ्लाइट से पाकिस्तान वापस चला गया।

'सार्क शिखर सम्मेलन' के दौरान जो कुछ हुआ वह सभी जानते है। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता कर रहे थे। 'सार्क शिखर सम्मेलन' की यह परम्परा है उसके नियमों में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि 'सार्क' के मंच से द्विपक्षीय मामले नहीं उठाये जायेंगे। इसके बावजूद पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज ने भारत–पाकिस्तान का मामला उठाया और नाटकीय अंदाज में भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी बाजपेयी से जाकर हाथ मिलाया। इससे बाजपेयी जी को कितनी विचित्र स्थिति का सामना करना पड़ा, यह सभी जानते है। उस समय पत्रकार–दीर्घा में उपस्थित कुछ लोगों ने जिस प्रकार तालियों की गड़गड़ाहट में पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का हौसला बढ़ाया, वह बड़ा अजीब लगा। उसी सम्मेलन में जब भारतीय प्रधानमंत्री बाजपेयी ने जनरल मुशर्रफ के कथन का उत्तर दिया तो दो एक पत्रकारों को छोड़कर किसी ने कोई तवज्जों नहीं दी। होना तो यह चाहिए था कि 'सार्क' के अध्यक्ष नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा को जनरल मुशर्रफ के भाषण के बाद यह कहना चाहिए था कि जनरल मुशर्रफ ने द्विपक्षीय सम्बन्धों के बारे में जो कुछ कहा वह कार्यवाही का हिस्सा नहीं होगा। परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसका कारण भी उस दिन उजागर हुआ जब सम्मेलन के दो चार दिन बाद उन्होंने अपने घर पर आमंत्रित पत्रकार वार्ता में स्पष्ट तौर पर कहा कि सार्क सम्मेलन के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री बाजपेयी और पाकिस्तानी राष्ट्रपति मुशर्रफ के बीच मुलाकात करा देना नेपाल की उपलब्धि है। जबकि नेपाल को यह अच्छी तरह मामूल था कि भारत 'सार्क' के दौरान भी जनरल मुशर्रफ से किसी प्रकार की भेंट या वार्ता से इन्कार करता रहा था। अगर कुछ लोगों ने इस घटना से यह निष्कर्ष निकाला कि नेपाल भारत के मुकाबले पाकिस्तान को बेहतर दोस्त मानता है, तो क्या आश्चर्य है ? इसी संदर्भ में प्रसंगवश एक और छोटी सी घटना का उल्लेख करना जरूरी है। प्रधानमंत्री बनने के कुद दिन बाद नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने सिंह दरबार स्थित अपने कार्यालय में भारतीय मीडिया के प्रतिनिधियों को बातचीत के लिए बुलाया है। मैं भी उसमें आमंत्रित था। मुझे इस बात की खुशी हो रही थी कि अच्छा है जो देउबा जी ने सबसे पहले भारतीय पत्रकारों को बुलाया। हम लोग उनके कार्यालय में प्रतीक्षा कर रहे थ कि मैं आश्चर्यचकित रह गया जब मैंने देखा कि दो पाकिस्तानी पत्रकार एक नेपाली पत्रकार के साथ प्रधानमंत्री के कमरे से बाहर निकल रहे थे। मेरा भ्रम टूट गया।

दिनांक 11 सितम्बर, 2001 को अमेरिका में 'विश्व व्यापार केन्द्र' पर हुए आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान तक ने अपने यहा चल रहे मदरसों को नियन्त्रित करने के लिए कानून बनाया। नेपाल ने भी देर से ही सही एक आदेश जारी करके उनकी गतिविधियों पर निगाह रखने का निर्णय लिया। परन्तु आगे कोई कार्यवाही नहीं हुई। सरकार के इस निर्णय की नेपाल–मुस्लिम इत्तिहाद संगठन ने जमकर आलोचना की। यह वही संगठन है जो नेपाल में कश्मीरी आतंकवादियों को संरक्षण देता है, ऐसा जानकार सूत्रों का कहना है। अमेरिका के विश्व–व्यापी आतंक विरोधी अभियान के बाद भारत और नेपाल के गृहसचिवों की बैठक में भी यह फैसला किया गया कि नेपाल अपने यहा मदरसों की गतिविधियों को नियमित करने के लिए कार्यवाही करेगा। काठमाण्डू स्थित 'हिन्दुस्तान टाइम्स' के संवाददाता केशव प्रधान ने 1 फरवरी, 2002 को लिखा कि "नेपाल के उत्तर प्रदेश और बिहार से लगी अपनी सीमा पर तेजी से बढ़ रहे मदरसों की गतिविधियों को नियन्त्रित करने का फैसला किया है, जिनके बारे में भारतीय खुफिया एजेन्सियों ने कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से वे खतरनाक है।" एक नेपाली अधिकारी ने कहा कि हमने सभी मदरसों से कहा है कि वे अपना रजिस्ट्रेशन कराये और एक माह के भीतर अपना हिसाब–किताब दे।"

नेपाल में मदरसों की संख्या 500 से ज्यादा है जिनमें अधिकांशतः भारत से लगे तराई क्षेत्र में है। वर्ष 1990 में बहुदलीय प्रजातन्त्र प्रणाली लागू होने के बाद नेपाल से गैर हिन्दू संगठनों पर लगा प्रतिबन्ध उठा लिया गया। इसके बाद भारत–नेपाल सीमा के दोनो ओर काफी संख्या में नई मस्जिदें बनी है। इस समय नेपाल में मुसलमानों की संख्या 20 लाख से ज्यादा है जो पिछले एक दशक में तीन गुना हो गई। भारतीय खुफिया एजेन्सियों को शक है कि इतनी भारी संख्या में मस्जिदों और मदरसों के निर्माण के पीछे आई.एस.आई. और खाड़ी देशों के कुछ देशों का हाथ है। 1 फरवरी, 2002 को 'काठमाण्डू पोस्ट' में कपिलवस्तु में इस समय चार बड़े रजिस्टर्ड मदरसे है और एक सौ से अधिक मदरसों ने रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन मदरसों को सऊदी अरब, कतर तथा यू0ए0ई0 से आर्थिक सहायता मिलती है। रिपोर्ट में मुस्लिम समुदाय के हवाले से कहा गया है कि विदेश से मिलने वाली आर्थिक सहायता का इन मदरसों में अच्छे कार्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाता है।" नेपाल सीमा से लगे भारतीय क्षेत्र मे भी मदरसों की कमी नहीं। परन्तु वहा भी सरकार उनकी जाँच पड़ताल नहीं कर पा रही है, वोट की राजनीति के कारण। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने कोलकाता में अमेरीकी कार्यालय के पास हुए विस्फोट के बाद इन मदरसों के बारे में कुछ कहा–दूसरे दिन ही उन्हें माफी मांगनी पड़ी। इन सब बातों से इतना तो निश्चित है कि नेपाल तथा सीमा के उस पार हाल के वर्षों में मुस्लिम शिक्षा के नाम पर ऐसी संस्थाओं की स्थापना हुई है, जिनकी गतिविधियाँ संदिग्ध है।

RRIJM 2015, All Rights Reserved

दिनांक 13 जनवरी, 2002 को 'एशियन ऐज' में राहुल दास की एक रिपोर्ट में कहा गया कि आई.एस.आई. नेपाल में इस्लामिक उग्रपंथी संगठनों की मदद कर रहा है। सिलीगुड़ी में गिरफ्तार पाकिस्तानी जासूस मोहम्मद दिलशाद ने पूरा ब्यौरा दिया कि किस प्रकार आई.एस.आई. के एजेन्ट नेपाल इसे भारत के खिलाफ आतंकवादी कार्यवाही चलाते है।

'चीन' के प्रधानमंत्री जू रोंगजी ने मई 2001 में अपनी काठमाण्डू यात्रा के दौरान 'स्याब्रूबेंसी' और 'रसुआगढ़ी' के बीच सड़क निर्माण करने के समझौते पर हस्ताक्षर किया। इससे नेपाल का तिब्बत क 'केरूंग क्षेत्र' से सीधा सम्पर्क हो जायेगा। 'राइजिंग नेपाल' (19.05.2001) में प्रकाशित एक लेख में चिरंजीवी पोडेल ने कहा कि "नेपाल और चीन के सम्बन्ध प्राचीन सभ्यता समान संस्कृति और धार्मिक परम्पराओं की ठोस नींव पर आधारित है और इनमें कभी उतार– चढ़ाव नहीं आया जो दोनों देशों के बीच सच्ची मैत्री प्रतीक है।"

उधर चीन ने ल्हासा तक ग्यारह सौ किलोमीटर लम्बी रेल लाइन का निर्माण शुरू कर दिया है, जो वर्ष 2007 तक बनकर तैयार हो जायेगी। तेरह हजार फीटर की ऊँचाई पर बनी यह रेल लाइन दुनिया की सबसे ऊँची रेल लाइन होगी। चीन के उप रेल मंत्री ने कहा कि "इस रेल लाइन का स्ट्रेटेजिक महत्व है और इसका आर्थिक, सैनिक तथा राजनीतिक दृष्टि से बड़ा महत्व है।" वैसे ल्हासा भले ही काठमाण्डू से दूर है परन्तु तिब्बत नेपाल की उत्तरी सीमा है। अतः तिब्बत में हो रहे परिवर्तन का नेपाल पर असर पड़ना स्वाभाविक है।

"नेपाल के लोग इस वजह से भी शंकालु हो जाते हैं कि भारतीय पुलिस यदाकदा नेपाल में बिना अनुमति क आ जाती है। वर्ष 1996 में भारत नेपाल के बीच 'महाकाली सन्धि' पर हस्ताक्षर किये गये। पाकिस्तान इसका प्रारम्भ से ही विरोध करता रहा है। अतः उसने इस संधि के विरोधी नेपाली नेताओं को सह देना शुरू कर दिया। उसका कारण थाा कि इस संधि से 'छमेलिया नदी' पर पाकिस्तान द्वारा प्रस्तावित बिजली धन पानी में डूब जाता। अतः पाकिस्तान शुरू से ही 'महाकाली संधि' के खिलाफ था।

एक दशक पहले तक नेपाल में कोई भारत विरोधी या पाकिस्तान समर्थक अखबार नहीं था। परन्तु दाऊद इब्राहिम जैसे लोगों ने नेपाली मीडिया को प्रभावित करने के लिए करोड़ो रूपया खर्च कर दिया है। नेपाल ने पाकिस्तान के साथ 'दौत्य–सम्बन्ध' इसलिए स्थापित किया कि वह तीन तरफ भारत से घिरे नेपाल की मदद करेगा। परन्तु पाकिस्तान ने अभी तक इस प्रकार की कोई सद्भावना नहीं दिखाई।"

इसी संदर्भ में पटना से प्रकाशित 'हिन्दुस्तान' की एक खबर भी पढ़ने लायक है–"अमेरीकी संसद में रिपब्लिकन पार्टी की एक शोध समिति ने अपनी रिपोर्ट 'न्यू इस्लामिक इन्टरनेशनल' में कहा कि पाकिस्तानी खुफिया एजेन्सी आई. एस.आई. नेपाल तथा बांग्लादेश स्थित अपने गुप्त प्रशिक्षण केन्द्रो के माध्यम से भारत के विभिन्न भागों में आतंकवाद तथा विनाशकारी गतिविधियों को फैलाने का प्रशिक्षण दे रही है। भारत–नेपाल खुली सीमा का लाभ उठाकर बड़ी संख्या में उपद्रवकारी भारत में घुसने में सफल रहे है। हाल के दिनांक में करीब दो दर्जन आतंकवादी पूर्वी चम्पारण तथा सीतामढ़ी जिलों में पकड़े गये है। पाकिस्तानी खुफिया एजेन्सी अब उत्तरी भारत के काफी बड़े क्षेत्र में अपना जाल फैलाने लगी है। नेपाल से लगी भारतीय सीमा में आई.एस.आई. सामाजिक एवं धार्मिक विद्वेष फैलाने के साथ इस्लामीरण का आधार भी तैयार कर रही है। एक सुनियोजित योजना के तहत नेपाल के कृष्णानगर, भालूगांव, नेपालगंज, जनकपुर और कलैया में आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर चलाये जा रहे है। इन शिविरों का संबंध नेपाल के माओवादियों से भी हो तो कोई आश्चर्य नहीं (हिन्दुस्तान, पटना 10 जुलाई 2001)। इस तरह नेपाल की सीमा से दूर रहते हुए भी पाकिस्तान की गतिविधियाँ भारत–नेपाल सम्बन्धों को प्रभावित करती है। भविष्य में इनका प्रभाव और बढ़ सकता है, इसमें कोई सन्देह नहीं।

पाकिस्तान खुफिया एजेन्सी (आई.एस.आई.) द्वारा पोषित इस्लामिक आतंकवाद ने आज के समय में विश्वस्तरीय रूप ले लिया है, भारत उनमें सबसे पीड़ित राष्ट्रों में एक है। भारत के लिए यह प्रमुख चुनौतियों में से एक है, क्योंकि भारत एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है जहा पर विभिन्न जाति, धर्म के लोग रहते है।

आतंकवाद के प्रसार में इस्लामिक कट्टरपंथी व आई.एस.आई. की अहम् भूमिका रही है वे आज भी शताब्दी पुरानी नीतियों पर चलने के लिए आतंक का माहौल विश्व भर में फैलाने का कार्य कर रहे है तथा उनका एक वृत्ति इस्लामिक राष्ट्र बनाने की महत्वकांक्षा है। साथ ही अन्य धर्मों को ना देखने की चाहत है। ऐसी स्थिति में वह धर्म, जाति, क्षेत्रीय अलगावं आदि को बढ़ावा देकर आतंक का माहौल बना रहे है तथा निर्दोष लोगों की विभिन्न माध्यमों से जान ले रहे है। उन्हें मानवता से कुछ सरोकार नहीं है। ऐसी स्थिति में लोगों व राष्ट्रों के मध्य तनाव की स्थिति बन जाती है।

भारत में उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी सीमा नेपाल के साथ लगती है। जिसका सामरिक प्रयोग आई.एस.आई. ने इस प्रदेश में अपना तन्त्रजाल फैलाने के लिए किया है। उत्तर प्रदेश में कई इस्लामी मदरसे पनप रहे है। जिसका उपयोग आई.एस.आई. ने अपने अड्डों के रूप में किया है। इनमें से अधिकांश मदरसों से संदिग्ध गतिविधियाँ चलाने वाले आतंकवादी संगठन जैसे– लश्कर–ए–तैय्यबा, हरकत–उल–अंसार, अलवर्क तंजीम, तंजीम–उल–जेहाद, जम्मू–कश्मीर लिब्रेशन फ्रन्ट और हिज्ब–उल–मुजाहिदीन, जैश–ए–मोहम्मद, जमात–उत–दावा इत्यादि (कुल 31) संबंधित पाये गये है। एक रिपोर्ट के अनुसार नेपाल में काठमाण्डू स्थित हिमालयन बैंक तथा पाकिस्तान का हबीब बैंक मदरसों और मस्जिदों के विकास और आई.एस.आई. की

गतिविधि के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश में धन खर्च कर रहा है। कारगिल युद्ध के दौरान भी हबीब बैंक उत्तर प्रदेश के आजमगढ़, मऊ, बहराइच, गोण्डा, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, महराजगंज तथा कुछ अन्य जिलों में भारत विरोधी काम के लिए धन खर्च करने की बात सामने आई है।

नेपाल में सटी सीमा होने के कारण आई.एस. आई. को भारत में जाली नोट, हथियार, विस्फोटक पदार्थ तथा मादक पदार्थों की तस्करी में आसानी होती है। उत्तर प्रदेश के रास्ते हथियारों एवं अन्य सामान को भारत के दूसरे भागों में पहुँचाया जाता है। 6 दिसम्बर 2000 को उत्तर प्रदेश पुलिस ने आई.एस.आई. के 5 'आपरेटिव' को गिरफ्तार किया तथा उनसे संवेदनशील कागजात एवं सामग्री बरामद की। यह लोग काठमाण्डू स्थित पाकिस्तानी दूतावास को संवेदनशील कागजात उपलब्ध करवाने वाले थे। इसी बीच 3 सित. 2000 को उत्तर प्रदेश पुलिस ने आगरा और अलगढ़ में दो हिज्ब–उल–मुजाहिदीन से सम्बन्धित आतंकवादियों को गिरफ्तार किया पूछताछ के दौरान इन आतंकवादियों ने फैजाबाद, लखनऊ और कानपुर में किये गये बम विस्फोटों में अपनी भूमिका को स्वीकार किया।

आई.एस.आई. ने उत्तर प्रदेश स्थित अलीगढ़ जिले में मुस्लिम विश्वविद्यालय में मुस्लिम छात्रों में भी अपनी पैठ गहराने के प्रयत्न किये है। अक्टूबर 2000 में आई.एस.आई. के एजेन्ट हाजी सुलेमान की गिरफ्तारी के उपरान्त उसके पास से कुख्यात आतंकवादी अजहर मसूद के भड़काऊ भाषणों की 13 कैसेट, कई हैंड ग्रेनेड और महत्वपूर्ण कागजात बरामद किये। गिरफ्तारी से पूर्व हाजी सुलेमान मेरठ, सहारनपुर, हरिद्वार, दिल्ली तथा हरियाणा की कई मस्जिदों में भड़काऊ भाषण दे चुका था।

भारत–नेपाल सीमा पर मदरसों एवं मस्जिदों का एक जाल सा बिछ गया है। इस क्षेत्र में 121 नये मदरसे एवं 146 मस्जिदें बनी है। भारत में उत्तर प्रदेश के तराई इलाके एवं पहाड़ी क्षेत्र में भी आई.एस.आई. ने अपनी पैठ बना ली है। इस प्रकार आई.एस.आई. ने अपना तन्त्रजाल भारत के प्रमुख शहरों में फैला रखा है। जहा इसके एजेन्ट सक्रिय रूप से भारत विरोधी गतिविधियों में संलग्न रहते है।

पाकिस्तान की खुफिया एजेन्सी आई.एस.आई. द्वारा भारत विरोधी कार्यों के लिए नेपाल की धरती के इस्तेमाल करने पर भारत ने नेपाल सरकार से गहरी चिन्ता जतायी। नेपाली प्रधानमंत्री श्री देउबा ने बातचीत में श्री सिन्हा को भरोसा दिलाया कि नेपाल सरकार इस मसले पर काफी गम्भीर है और वह किसी भी सूरत में नेपाली धरती को भारत के विरूद्ध इस्तेमाल नहीं होने देगी। इस वार्ता के दौरान दोनो देशों में आई.एस.आई. की गतिविधियों को रोकने और उसकी निगरानी के लिए सहमति व्यक्त की गई। काठमाण्डू की यात्रा से लौटते समय विदेशमंत्री श्री यशवन्त सिन्हा ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि 1800 किलोमीटर लम्बी और खुली सीमा होने के कारण हमने सीमा पर और अधिक निगरानी बढ़ाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि नेपाल सरकार अपने देश में आई.एस.आई. की गतिविधियों को कुचलने के लिए पहले ही संकल्प व्यक्त कर चुकी है। श्री सिन्हा ने आगे कहा कि दोनों की पक्षों ने संदिग्ध रूप से पाकिस्तान से आ रही जाली भारतीय मुद्रा की भी समस्या पर विचार किया। हमें इस बारे में जानकारी है और नेपाल सरकार भी इन सबसे अवगत है, उन्होंने जोर देकर कहा कि यह भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने की साजिश है। सिन्हा के अनुसार दोनों ही देश जाली व्यापार से प्रभावी रूप से निपटने के लिए सहमत थे।

अब धीरे–धीरे स्थिति ऐसी बनती जा रही है कि माओवादी पाकिस्तानी खुफिया एजेन्सी आई.एस.आई. से भी अपने सम्पर्क बढ़ा रहे हैं। नेपाल के 23 से अधिक जनपदों में आई.एस.आई. के लड़ाकू (दस्तक) सक्रिय हैं और इन दस्तकों को नेपाल की राजधानी काठमाण्डू स्थित पाकिस्तानी दूतावास से सब प्रकार की सहायता मिलती है।

पिछले अनेक वर्षों के अनुभव से यह बात स्पष्ट होती जा रही है कि पाकिस्तानी आतंकवादी जो जम्मू–कश्मीर में खून की होली खेल रहे है। उनके तार नेपाल के कट्टरपंथियों से भी जुड़ गये है। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री गिरिजाप्रसाद कोइराला दो वर्ष पूर्व भारत आये थे, तब उनसे यह साफ–साफ कह दिया गया था कि वह नेपाल में पाकिस्तान की भारत विरोधी गतिविधियों पर रोक लगाये। दिसम्बर 1999 में जिस भारतीय विमान का आतंकवादियों ने अपहरण किया था और कंधार ले जाकर अनेक भारतीयों को बन्धक बनाकर रखा था, इस विमान अपहरण की धटना की शुरूआत काठमाण्डू से ही हुई थी। भारत चाहता है कि नेपाल सरकार आई.एस.आई. की भारत विरोधी गतिविधियों पर सख्ती से रोक लगाये। इस संदर्भ में भारत ने कई मंचो से अपनी आवाज उठायी है। जनवरी 2002 के सार्क सम्मेलन में भारत के विदेश मंत्री जसवन्त सिन्हा ने काठमाण्डू से सार्क देशों से या दक्षिण एशिया के देशों से आतंकवाद के विरूद्ध संगठित होकर लड़ाई लड़ने का प्रस्ताव किया है। नेपाल एवं अन्य देश भारत की मांग का समर्थन करते है लेकिन पाकिस्तान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आतंकवाद को समर्थन दे रहा है।

गरीबी, आतंकवाद, पर्यटन, स्वास्थ्य आदि की अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर सार्क बैठक 21–22 अगस्त को पुनः काठमाण्डू में आयोजित की गई है। इस बैठक में आतंकवाद से सख्ती से निपटने के लिए कड़े कानून बनाने पर सहमति हुई और भारत के विदेश मंत्री यशवन्त सिन्हा व नेपाल के प्रधानमंत्री श्री शेरबहादुर देउबा ने आतंकवाद के खिलाफ दक्षेस के कानूनों को लागू करने पर जोर दिया। इस बैठक में भारत के विदेश मंत्री ने आई.एस.आई. द्वारा भारत विरोधी कार्यों के लिए नेपाल की धरती के इस्तेमाल करने पर नेपाल सरकार से गहरी चिन्ता जताई। उन्होंने माओवादियों के

RRIJM 2015, All Rights Reserved

मुकाबले में नेपाल सरकार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। नेपाली प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउबा ने भारतीय विदेश मंत्री को यह भरोसा दिलाया कि नेपाल अपनी धरती को भारत के खिलाफ पाकिस्तानी आतंकवादी/आई.एस.आई. को इस्तेमाल नहीं करने देगा।

इस प्रकार दोनों देश हिंसा और आतंकवाद के प्रश्न पर एक होकर कार्य करने की सिद्धान्ततः घोषणा के तहत प्रतिबद्ध है, लेकिन व्यवहार में ऐसा सम्भव नहीं हो पाता, क्योंकि नेपाल में माओवादियों का वहाँ के जनमानस पर अत्यधिक प्रभाव है। वहाँ का एक बहुत बड़ा वर्ग उन्हें समर्थन भी देता है उनकी अधिकांश मांगे उग्र राष्ट्रवादिता पर आधारित एवं भारत विरोधी होती है, इसलिए कोई भी सत्ता उनका खुलकर विरोध नहीं कर पाती। इसी कारण नेपाल में माओवादी हिंसा पर प्रभावकारी नियन्त्रण लगा पाना कठिन हो जाता है। कभी–कभी नेपाली इसके लिए भारत को भी दोषी ठहराने से नहीं चूकते हैं, क्योंकि भारत और नेपाल के मध्य 1800 किलोमीटर लम्बी और खुली सीमा होने के कारण ये हिंसावादी लोग हिंसात्मक क्रिया–कलाप करके भारत में आ जाते हैं और फिर कुछ समय गुजारकर नेपाल वापस चले जाते हैं। भारत से इन्हें अस्त्र–शस्त्र, गोला बारूद आदि विध्वंसक सामग्री भी छिपे रास्तों से एवं अनाधिकृत रूप से प्राप्त हो ही जाती है। इस प्रकार यदा–कदा भारत द्वारा भी नेपाल पर यह आरोप लगाया जाता है कि नेपाल में भारत विरोधी हिंसक तत्व सक्रिय देखे जा सकते हैं, जो आई.एस. आई. अथवा आतंकवादियों के माध्यम से भारत को अस्थिर करने के लिए षड्यन्त्र रचते हैं। अतः आतंकवाद दोनों देशों के मध्य घनिष्ठ सम्बन्ध कायम करने के रास्ते में एक बहुत बड़ी रूकावट के रूप में देखा जा सकता है।

निष्कर्षः–

भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय साख को गिराने के ऐसे प्रयत्न किये जा रहे हैं जिस कारण भारतीय सुरक्षा तन्त्र को और अधिक सचेत रहने की आवश्यकता है तथा भारतीय विरोध में शामिल संगठनों को प्रतिबन्धित करना आवश्यक है तथा भारतीय इन सब घटनाओं में शामिल ना हो इसके लिए आवश्यक कदम उठाने की जरूरत है। क्योंकि भारत विरोधी संगठन विभिन्न भागों में ऐसी अराजकता की स्थिति बनाना चाहते हैं, जो भारतीय स्थिति के लिए सहज ना हो। इसके लिए आवश्यक है कि एक संघीय एजेन्सी का गठन हो तथा भारतीय विदेश नीति को ऐसा वातावरण बनाने की आवश्यकता है कि "आतंकवाद के विरूद्ध सभी राष्ट्र जमीनी हकीकत को समझते हुए निष्पक्ष रूप से सहयोग दें व कार्यवाही करें। क्योंकि आतंकवाद की प्रति तुष्टीकरण से आतंकवादी को ही बढ़ावा मिल रहा है।"

संदर्भः

1. राम सागर शुक्ल, अंजान पड़ोसी, भारत, नेपाल, सनातन प्रकाशन, लखनऊ, 2004, पृ0–54
2. वही–
3. वही, पृ0–55
4. दैनिक हिन्दुस्तान, 17 जुलाई, 2000
5. दैनिक जागरण, दिल्ली, 7 सितम्बर, 2000
6. हिन्दुस्तान टाइम्स, 4 अक्टूबर, 2000
7. दैनिक हिन्दुस्तान, 17 जुलाई, 2000
8. दैनिक जागरण, दिल्ली, 7 सितम्बर, 2001
9. अमर उजाला, दिल्ली, 2 जनवरी, 2002
10. दैनिक जागरण, दिल्ली, 22 अगस्त, 2002
11. दैनिक जागरण, आगरा, 24 अगस्त, 2002
12. वही–
13. वही–
14. दीक्षित, जे.एन. भारत की विदेश नीति, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली, 2006, पृ.–61

RRIJM 2015, All Rights Reserved